



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 7 जनवरी, 2015

(पौष 17, 1936 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम	
	हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 31) (केवल हिन्दी में)	1
भाग-II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं	
भाग-IV	शुद्धि-पर्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

Price : Rs. 5.00

(ii)

भाग - I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 जनवरी, 2015

संख्या लैज़० 38/2014.—दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 30 दिसम्बर, 2014, की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 31

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003,

को आगे संशोधित

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 59 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

2003 के हरियाणा अधिनियम 6 में धारा 59क का रखा जाना।

“59क. माफी स्कीम.—इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे कर, जो ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्वधीन प्रथम अप्रैल, 2014 से पूर्व की अवधि के लिए बकाया हैं और विभिन्न प्रयासों के बावजूद उनकी वसूली होनी मुश्किल है, के पुराने बकायों की वसूली हेतु माफी स्कीम अधिसूचित कर सकती है।”।

3. (1) हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

रमेन्द्र जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।